Indian Economy(1950-1990)

After studying this chapter, the learners will

- **come to know the goals of India's five year plans**
- **know about the development policies in different sectors such as agriculture and industry from 1950-1990**
- **learn to think about the merits and limitations of a regulated economy.**

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप

- भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे;
- वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रकों, जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझंगे;
- एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे।

Indian Economy(1950-1990)

The central objective of Planning in India... is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life. First Five Year Plan

भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य.... विकास की एक एसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नये अवसर उपलब्ध करायेगी।

Introduction

On 15 August 1947, India woke to a new dawn of freedom. Finally we were masters of our own destiny after some two hundred years of British rule; the job of nation building was now in our own hands. The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few.

15 अगस्त, 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंतत: दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव-निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कानै-सी आथिर्क प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी।

Introduction

Socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. However, he was not in favour of the kind of socialism established in the former Soviet Union where all the means of production, i.e. all the factories and farms in the country, were owned by the government. There was no private property

जवाहरलाल नेहरु को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे, जिसमें उत्पादन के सभी साधन (खेत और कारखाने) सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी।

Introduction

Nehru, and many other leaders and thinkers of the newly independent India, sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism.

India would be a socialist society with a strong public sector but also with private property

नेहरु तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव-स्वतंत्र भारत के लिए पूँजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। भारत एक एसा समाजवादी समाज होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा।

Introduction

In a market economy, also called capitalism, only those consumer goods will be produced that are in demand, i.e., goods that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign markets.

बाज़ार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाज़ार में माँग हो इसमें, वही वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाज़ारों में सलाभ बेचा जा सके।

Introduction

In a capitalist society the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need but on the basis of Purchasing Power—the ability to buy goods and services.

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय-क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं।

Introduction

In a socialist society the government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of society. It is assumed that the government knows what is good for the people of the country and so the desires of individual consumers are not given much importance. The government decides how goods are to be produced and how they should be distributed.

समाजवादी समाज में सरकार ही यह निणर्य लेती है कि समाज की आवश्यकताओंके अनसुार भिन्न वस्तआु ंका उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए

Introduction

Mixed economies, i.e. the government and the market together answer the three questions of what to produce, how to produce and how to distribute what is produced. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do.

मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, अर्थात् सरकार तथा बाज़ार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है, जिन्हें बाज़ार सुलभ कराने में विफल रहता है।

Introduction

In India plans were of five years duration and were called five year plans (we borrowed this from the former Soviet Union) This long-term plan is called 'perspective plan'. The five year plans were supposed to provide the basis for the perspective plan.

भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएँ कहा जाता था (यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ही ली गई थी) इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

THE GOALS OF FIVE YEAR PLANS

The goals of the five year plans were: growth, modernisation, self-reliance and equity. This does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals

पंचवषीर्य योजनाओ के लक्ष्य थे संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्त्व दिया गया है।

Introduction

The 'Industrial Policy Resolution' of 1948 and the Directive Principles of the Indian Constitution reflected this outlook. In 1950, the Planning Commission was set up with the Prime Minister as its Chairperson. The era of five year plans had begun.

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ।

THE GOALS OF FIVE YEAR PLANS

Growth: It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. It implies either a larger stock of productive capital, or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services.

सवंृद्धिः इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूँजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूँजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है।

Mahalanobis: the Architect of Indian Planning

The name of the statistician, Prasanta Chandra Mahalanobis, Planning, in the real sense of the term, began with the Second Five Year Plan. The Second Plan, a landmark contribution to development planning in general, laid down the basic ideas regarding goals of Indian planning; this plan was based on the ideas of Mahalanobis. In that sense, he can be regarded as the architect of Indian planning.

उनमें सांख्यिकीविद् प्रशांतचन्द्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारिक विचार दिये गये हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में, उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है।

Mahalanobis: the Architect of Indian Planning

Mahalanobis was born in 1893 in Calcutta. He was educated at the Presidency College in Calcutta and at Cambridge University in England.

महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता (कोलकाता) तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में हुई।

Mahalanobis: the Architect of Indian Planning

Mahalanobis was born in 1893 in Calcutta. He was educated at the Presidency College in Calcutta and at Cambridge University in England. In 1945 he was made a Fellow (member) of Britain's Royal Society, one of the most prestigious organisations of scientists; only the most outstanding scientists are made members of this Society.

महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता (कोलकाता) तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में हुई। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो (सदस्य) बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है; जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है।

Mahalanobis: the Architect of Indian Planning

Mahalanobis established the Indian Statistical Institute (ISI) in Calcutta and started a journal, Sankhya, which still serves as a respected forum for statisticians to discuss their ideas.

महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई.एस.आई) स्थापना की तथा 'सांख्य' नामक एक जर्नल निकाला, जो आज भी साख्यिकीविदों के लिये परस्पर विचार-विमर्श के लिये एक प्रतिष्ठित मंच बना हआु है।

Mahalanobis: the Architect of Indian Planning

During the second plan period, Mahalanobis invited many distinguished economists from India and abroad to advise him on India's economic development. Many economists today reject the approach to planning formulated by Mahalanobis but he will always be remembered for playing a vital role in putting India on the road to economic progress, and statisticians continue to profit from his contribution to statistical theory

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किये जाने की सलाह दी। आज अनेक अथर्शास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिये उन्हें सदैव स्मरण किया जायेगा। सांख्यिकीविद् सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे।

The Service Sector

The share of agriculture declines and the share of industry becomes dominant. At higher levels of development, the service sector contributes more to the GDP than the other two sectors. In India, the share of agriculture in the GDP was more than 50 per cent—as we would expect for a poor country. But by 1990 the share of the service sector was 40.59 per cent, more than that of agriculture or industry, like what we find in developed nations. This phenomenon of growing share of the service sector was accelerated in the post 1991 period (this marked the onset of globalisation in the country

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुँच कर जी.डी.पी. में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाता है। भारत में, जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जी.डी.पी. में कृषि का अंश 50 प्रतिशत से अधिक था। किंतु, 1990 में सेवा क्षेत्रक का अंश बढ़कर 40.59 प्रतिशत हो गया– यह कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। एसी स्थिति तो प्राय: विकसित देशों में ही पायी जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्रक के अंश की संवृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ।

The Service Sector

The GDP is the market value of all the goods and services produced in the country during a year The GDP of a country is derived from the different sectors of the economy, namely the agricultural sector, the industrial sector and the service sector. The contribution made by each of these sectors makes up the structural composition of the economy.

जी.डी.पी. एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाज़ार मूल्य होता है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं– कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढाँचा तैयार होता है।

The Service Sector

Modernisation: To increase the production of goods and services the producers have to adopt new technology. Adoption of new technology is called modernisation. modernisation does not refer only to the use of new technology but also to changes in social outlook such as the recognition that women should have the same rights as men. A modern society makes use of the talents of women in the work place — in banks, factories, schools etc.

आधुनिकीकरण: वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर– बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है।

The Service Sector

Self-reliance: A nation can promote economic growth and modernisation by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first seven five year plans gave importance to self-reliance which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food.

आत्मनिर्भरता: कोई राष्ट आधुनिकीकरण और आर्थिक संवृद्धि, अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्त्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए, जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को, विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया।

The Service Sector

It was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies.

यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूँजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी।

The Service Sector

Equity: Now growth, modernisation and self-reliance, by themselves, may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of its people living in poverty. growth, modernisation and self-reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education and health care and inequality in the distribution of wealth should be reduced.

समानता: केवल सवंृद्धि, आधुनिकीकरण आरै आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च संवृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। संवृद्धि, आधुनिकीकरण आरै आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समानता भी महत्त्वपूर्ण है प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ जसैी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएँ भी कम होनी चाहिए।

The Service Sector

First seven five year plans, covering the period 1950-1990, attempted to attain these four goals and the extent to which they succeeded in doing so, with reference to agriculture, industry and trade.

1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन चार लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहां तक सफल रहे।

LAND CEILING

Land reforms and promoting the use of 'High Yielding Variety' (HYV) seeds which ushered in a revolution in Indian agriculture.

Land Reforms: At the time of independence, the land tenure system was characterised by intermediaries variously called zamindars, jagirdars etc.)

भू–सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। भू–सुधार: स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू–धारण पद्धति में जमींदार–जागीरदार आदि का वर्चस्व था।

LAND CEILING

Was another policy to promote equity in the agricultural sector. This means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands.

दरअसल समानता को बढ़ाने के लिये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है– किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू–स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था।

LAND CEILING

The abolition of intermediaries meant that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government – they were thus freed from being exploited by the zamindars. The ownership conferred on tenants gave them the incentive to incrase out put and this contributed to growth in agriculture.

बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकरों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किये जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू–स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानताके लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े–बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा।

LAND CEILING

The poorest of the agricultural labourers (such as sharecroppers and landless labourers) did not benefit from land reforms.

कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों (जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक) को भूमि-सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ।

LAND CEILING

The legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landholders to retain their land. Land reforms were successful in kerala and west Bengal because these states had governments committed to the policy of land to the tiller.

कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमीदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं, इसी कारण इन प्रांतों में भू–सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली।

The Green Revolution

At independence, about 75 percent of the country's population was dependent on agriculture. Productivity in the agricultural sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmer.

स्वतंत्रता के समय देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्रक में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था।

The Green Revolution

The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the green revolution.

यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थीं। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया।

The Green Revolution

The large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety (HYV) seeds especially for wheat and rice.

इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों **(HYV)** के प्रयोग से है, विशेषकर गेहू तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से

The Green Revolution

The farmers who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertiliser and pesticide.

बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी।

The Green Revolution

First phase of the green revolution (approximately mid 1960s upto mid 1970s), the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab. Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

अत: हरित क्रांति के पहले चरण में (लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक) **HYV** बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा।

The Green Revolution

In the second phase of the green revolution (mid-1970s to mid -1980s). The HYV technology spread to a larger number of states and benefited more variety of crops. The spread of green revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains: We no longer had to be at the mercy of America, or any other nation for meeting our nation's food requirements.

हरित क्रांति के द्वितीय चरण (1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक) में **HYV** बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुँचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधीद आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे।

The Green Revolution

The portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus. A good proportion of the rice and wheat produced during the green revolution period (available as marketed surplus) was sold by the farmers in the market

यदि किसान बाज़ार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करें, तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाज़ार में बेच सकें, तो अधिक उत्पादन का निश्चिय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाज़ार में बेचा गया अंश ही 'विपणित अधिशेष' कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाज़ार में बेच रहे थे।

The Green Revolution

The green revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage.

हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था।

The Green Revolution

The government provided loans at a low interest rate to small farmers and subsidised fertilisers so that small farmers could also have access to the needed inputs. Since the small farmers could obtain the required inputs, the output on small farms equalled the output on large farms in the course of time.

सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिये और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सकें। छोटे किसानों को, इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई।

The Debate Over Subsidies

The economic justification of subsidies in agriculture is, at present, a hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular

आजकल कृषि क्षेत्रक को दी जा रही आर्थिक सहायिकी का आर्थिक औचित्य एक गरमा–गरम बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्यत: छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई **HYV** प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायिकी दी जानी आवश्यक थी।

The Green Revolution

Subsidies are meant to benefit the farmers but a substantial amount of fertiliser subsidy also benefits the fertiliser industry; and among farmers, the subsidy largely benefits the farmers in the more prosperous regions.

यद्यपि सहायिकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुँचाना है, किंतु उर्वरक-सहायिकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुँचता है।

The Green Revolution

On the other hand, some believe that the government should continue with agricultural subsidies because farming in India continues to be a risky business.

छूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि–सहायिकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है।

The Green Revolution

Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers and violate the goal of equity.

सहायिकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़गी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा।

The Green Revolution

1960s, Indian agricultural productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains.

1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया।

The Green Revolution

Some 65 per cent of the country's population continued to be employed in agriculture even as late as 1990.

इसके बावजूद, नकारात्मक पहलू यह रहा है कि 1990 तक भी देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी थी।

The Green Revolution

The proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of population working in the sector declines considerably. In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly but not the population depending on it (67.5 per cent in 1950 to 64.9 per cent by 1990)

कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950–90 की अवधि में यद्यपि जी.डी.पी. में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं (जो 1950 में 67.50 प्रतिशत थी और 1990 तक घटकर 64.90 प्रतिशत ही हो पाई)।

Industry And Trade

Economists have found that poor nations can progress only if they have a good industrial sector. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture; it promotes modernisation and overall prosperity.

अर्थशास्त्रियों ने एसा पाया है कि निर्धन राष्ट तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

Industry And Trade

The variety of industries was very narrow — largely confined to cotton textiles and jute. There were two wellmanaged iron and steel firms — one in Jamshedpur and the other in Kolkata — but, obviously, we needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was to grow.

अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था, तो हमें एसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों।

Public And Private Sectors In Indian Industrial Development

The role of the government and the private sector in industrial development? At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of Indian economy; nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so.

औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्रक की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूँजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाज़ार भी नहीं था, जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास एसा करने के लिए पूँजी भी थी

Public And Private Sectors In Indian Industrial Development

Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding heights of the economy, as the Second Five Year plan put it. This meant that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. The policies of the private sector would have to be complimentary to those of the public sector, with the public sector leading the way

भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्रक की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्रक की नीतियों की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्रक अग्रणी भूमिका निभायेगा।

Public And Private Sectors In Indian Industrial Development

In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. This resolution formed the basis of the Second Five Year Plan, the plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society

भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया

Industrial Policy Resolution 1956 (IPR 1956)

industries into three categories. The first category comprised industries which would be exclusively owned by the government; the second category consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the public sector, with the government taking the sole responsibility for starting new units; the third category consisted of the remaining industries which were to be in the private sector.

उद्योगों को तीन वगों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे, जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे, जिनके लिए निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ मिल कर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे, जो निजी क्षेत्रक के अंतर्गत आते थे।

Industrial Policy Resolution 1956 (IPR 1956)

This policy was used for promoting industry in backward regions; it was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area

इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए, तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था।

Industrial Policy Resolution 1956 (IPR 1956)

The purpose of this policy was to promote regional equality

ठस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था

Industrial Policy Resolution 1956 (IPR 1956)

What the economy required. License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods.

इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था, जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है।

Small-scale Industry

In 1955, the Village and Small-Scale Industries Committee, also called the Karve Committee, noted the possibility of using small-scale industries for promoting rural development. A 'small-scale industry' is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit.

1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिये जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है।

Small-scale Industry

It is believed that small-scale industries are more 'labour intensive' i.e., they use more labour than the large-scale industries and, therefore, generate more employment

एसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम–प्रधान होते हैं, अर्थात् उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं।

Small-scale Industry

They were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at lower interest rates.

उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थीं जैसे, कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक-ऋण।

Trade Policy: Import Substitution

The industrial policy that India adopted was closely related to the trade policy. In the first seven plans, trade was characterised by what is commonly called an inward looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution.

भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात–प्रतिस्थापन कहा जाता है।

Trade Policy: Import Substitution

In this policy the government protected the domestic industries from foreign competition. Protection from imports took two forms: tariffs and quotas.

ठस नीति के अनुसार, सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के दो प्रकार थे: प्रशुल्क और कोटा।

Trade Policy: Import Substitution

Tariffs are a tax on imported goods; they make imported goods more expensive and discourage their use.

प्रशुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएँ अधिक महँगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं।

Trade Policy: Import Substitution

The policy of protection was based on the notion that industries of developing countries were not in a position to compete against the goods produced by more developed economies.

संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था।

Effect Of Policies On Industrial

The achievements of India's industrial sector during the first seven plans are impressive indeed. The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13 per cent in 1950-51 to 24.6 per cent in 1990-91.

प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्रक की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रक द्वारा प्रदत्त जी.डी.पी. का अनुपात 1950-51 में 13 प्रतिशत से बढकर 1990-91 में 24.6 प्रतिशत हो गया। जी.डी.पी. से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

Effect Of Policies On Industrial

No longer was Indian industry restricted largely to cotton textiles and jute; in fact, the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector

अब भारतीय उद्योग मोटे तौर पर सूती वस्त्र और जूट तक सीमित नहीं था; वास्तव में, औद्योगिक क्षेत्र 1990 तक अच्छी तरह से विविध हो गया, मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के कारण

Effect Of Policies On Industrial

Protection from foreign competition enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed.

विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों के विकास को सक्षम किया जो अन्यथा विकसित नहीं हो सकते थे।

Effect Of Policies On Industrial

The point is that after four decades of Planned development of Indian Economy no distinction was made between (i) what the public sector alone can do and (ii) what the private sector can also do.

मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के चार दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि (क) केवल सार्वजनिक क्षेत्रक क्या कर सकता है और (ख) निजी क्षेत्रक भी क्या कर सकता है?

Effect Of Policies On Industrial

Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources. This does not mean that private firms are always profitable (indeed, quite a few of the public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses; they were then nationalised to protect the jobs of the workers).

अनेक सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। भले ही इसके कारण राष्ट के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो (वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्में मूलत: निजी फर्में थीं, जो हानि के कारण बंद होने को थीं।) उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

Effect Of Policies On Industrial

The excessive regulation of what came to be called the permit license raj prevented certain firms from becoming more efficient.

बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नही बन पाई।

Effect Of Policies On Industrial

The protection from foreign competition was also being criticised on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good. Due to restrictions on imports, the Indian consumers had to purchase whatever the Indian producers produced.

विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा, जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था, जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे।

Effect Of Policies On Industrial

A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of the nation. The public sector firms, on this view, should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of people and not on the profits they earn.

कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाये गये लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

Effect Of Policies On Industrial

Owing to all these conflicts, economists called for a change in our policy. This, alongwith other problems, led the government to introduce a new economic policy in 1991.

इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की।

Conclusion

The progress of the Indian economy during the first seven plans was impressive indeed. Our industries became far more diversified compared to the situation at independence. India became self- sufficient in food production thanks to the green revolution. Land reforms resulted in abolition of the hated zamindari system.

प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गये। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया!

Conclusion

Excessive government regulation prevented growth of entrepreneurship. In the name of selfreliance, Indian producers were protected against foreign competition and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produced. Indian policies were 'inward oriented' that failed to develop a strong export sector.

अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यमवृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थीं, उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्रक विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है